MR. CHAIRMAN: Hon. Members, as announced in the House yesterday, there will no lunch recess today. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, I have received notices under Rule 267... ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, what Business will be transacted at 1 o'clock? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It has already been communicated. Hon. Minister will reply. I had indicated it in detail yesterday. I am only reiterating it for the benefit of Members. Hon. Members, the notice received under Rule 267 is not in accord and hence declined. Now, Shri Pramod Tiwari to raise the issue of flood situation in the State of Uttarakhand and Himachal Pradesh.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Incidents of multiple cloud bursts in Shimla, Mandi and Kullu districts of Himachal Pradesh and Uttrakhand

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): सभापति महोदय, बारिश ने हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिले में जमकर कहर बरपाया है, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई है और करीब 50 लोग लापता हैं। महोदय, श्रीखंड महादेव मार्ग पर भीमडवारी में करीब 250 लोग अभी भी फंसे हुए हैं तथा एक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र तथा दो विद्युत परियोजनाएँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस तरह से उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, चमोली और टिहरी में बादल फटने से तबाही हुई है, जिसमें करीब 16 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के लापता होने की भी सूचना मिली है। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला पैदल रास्ता बह जाने से प्रशासन ने फिलहाल यात्रा रोक दी है। हिमाचल व उत्तराखंड में बादल फटने की अनेक घटनाओं की वजह से लगभग 22 लोगों की मौत हो गई है, करीब 60 लोग लापता हैं और लगभग 50 घर बह गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस होम गार्ड और फायर सर्विसेज की टीमें राहत, खोज और बचाव कार्य में जुटी हैं।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

महोदय, प्रकृति से बार-बार छेड़छाड़ करने के कारण बादल फटने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की सबसे अधिक घटनाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में दसकीय तापमान वृद्धि, वैश्विक तापमान वृद्धि की दर से अधिक है। बादल फटने के कारण फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और लैंडकेविंग की घटनाएं हो जाती हैं। बादल फटने की संभावनाओं का पता करने के लिए अत्याधुनिक राडार के एक बेहतर नेटवर्क की

आवश्यकता होती है, जो कि अपेक्षाकृत काफी महंगा है। सरकार को इस सिलसिले में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भारत में यद्यपि प्राकृतिक घटनाएं अधिक घटित होती हैं, तथापि देश में संरचना योजना, प्रबोधन बचाव कार्य, आपदा के पश्चात विकास कार्य और आपदा के पूर्व तैयारी इत्यादि क्षेत्रों में सामान्यतः कमी पाई जाती है। अतः मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक रचनात्मक कार्यक्रम बनाए तथा दोनों राज्य सरकारों को इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराए। चूँकि पिछली बार हिमाचल में जो विनाश लीला हुई थी, उस पर केंद्र सरकार ने यथोचित धनराशि आज तक नहीं दी है। महोदय, मेरा कहना है कि राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि क्षति के आधार पर क्षतिपूर्ति की जाए और हिमाचल प्रदेश के लिए एक पैकेज की व्यवस्था की जाए - यह मेरा आपसे आग्रह है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Pramod Tiwari: Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Now, Shri Tiruchi Siva. Demand to save gig and online platform workers from exploitative practices.

Demand to safeguard Gig and Online Platform Workers from exploitative practices

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I would like to draw the attention of the Government towards the need to evolve solutions to safeguard the gig and online platform workers from exploitative practices by some private companies. Sir, it is a very important issue.

Gig economy offers flexibility and income opportunities to nearly 80 lakh workers as of now, and, it is expected to rise up to 2.3 crore by 2030 as per the NITI Aayog Report. But these workers are vulnerable to unfair treatment and insufficient protection. The pandemic has revealed a very significant role of the gig workers. They played a role in the economy by virtue of their roles as drivers, delivery persons and agents. Who are gig workers is the question. They comprise of those who are working in Swiggy, Zomato, Dunzo, Ola, Uber, etc. Around 80 lakh such workers are there. They ensured the basic necessity of the people when the whole world was locked inside. They played a very great role at that time. But the recent reports highlight the precarious conditions faced by these workers. For instance, delivery persons failing to meet certain targets have seen their health insurance coverage reduced or even revoked, placing them and their families at significant risk in the event of medical emergencies. This is at odds with global standards. For instance, food delivery platforms around the globe offer accident coverage to gig workers without any gratiification. Insecurity of employment is an impediment for these